ASSENT TO BILLS

SECRETARY: Sir, I lay on the Table following two Bills passed by the Houses of Parliament during the current session and assented to since a report was last made to the House on the 2nd May, 1979:—

1 The Appropriation (No. 3) Bill, 1979.

2. The Merchant Shipping (Amendment) Bill, 1979.

12.42 hrs.

CALLING ATTETION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

REPORTED DEMONSTRATION BY RAILWAY EMPLOYEES TO PRESS THEIR DEMANDS FOR BONUS.

श्रीमती मृणाल गोरे (बम्बई-उत्तर) : अध्यक्ष महोदय, मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर रेल मंत्री का ध्यान दिलाती हूं और प्रार्थना करती हूं कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें :

"अखिल भारतीय रेल कर्मचारियों द्वारा बोनस की अपनी माग के समर्थन में किए गए प्रदर्शन के समाचार।"

12.43 hrs

[MR DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

रेल मंत्री (प्रो० मधु दंडवते) : कुछ समय पहले से रेल कर्मचारियों के विभिन्न वर्गों द्वारा विविध मंचों से बोनस की मांग उठायी गयी है। नयी दिल्ली में आल इंडिया रेलवेमेन फैडरेशन द्वारा रेल कर्मचारियों को बोनस दिये जाने की अपनी माग मनवाने के लिए 7 मई को और भारतीय रेल मजदूर संघ द्वारा मान्यता के साथ-साथ बोनस दिये जाने के प्रश्न पर 8 मई को प्रदर्शन किये गये।

इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस से संबंद्ध नेशनल फैडरेशन आफ इंडियन रेलवे मैन ने 25 मार्च, 1979 को हुई अपनी कार्यकारिणी की बैठक में हड़ताल का बैलट लेने के बाद एक प्रस्ताव पारित किया और अपनी सभी संबंद्ध यूनियनों को निर्देश दिया कि वे पहली मई, 1979 को बोनस और अन्य मांगो के प्रश्न पर अपने-अपने क्षेत्रीय रेल प्रशासनो को 31 मई, 1979 की मध्य रात्रि से पूर्ण हड़ताल पर जाने का नोटिस दे दें। लेकिन, 29 अप्रैल, 1979 को पारित एक अन्य प्रस्ताव के द्वारा नेशनल फैडरेशन आफ इंडियन रेलवेमैन ने हड़ताल की अपनी योजना को जुलाई, 1979 के अन्त तक के लिए स्थगित कर दिया है।

आल इंडिया रेलवेमैन फैडरेशन ने अपनी जनरल काउंसिल मिटिंग में 9 मई, 1979 को निर्णय किया है कि अगस्त, 1979 के अन्त तक हड़ताल के मतदान का काम पूरा कर लिया जाये और यदि इस बीच सरकार बोनस के प्रश्न पर कोई निर्णय नही लेती तो उसके बाद आगे की कार्यवाही के बारे में निर्णय लेने के लिए उनकी कार्यकारी की समिति की बैठक की जायेगी।

आल इंडिया रेलवे एम्पलाइज कानफैडरेशन ने, जो मान्यता प्राप्त यूनियन नही है, बोनस की माग सहित एक माग पत्र प्रस्तुत किया है। इस संगठन ने अब तक 8 मई, 1979 के 00 00 बजे से "नियमानुसार कार्य" करने का आन्दोलन शुरू कर दिया है।

रेल कर्मचारियों की दो मान्यता प्राप्त फैडरेशन—आल इंडिया रेलवेमैन फैडरेशन और नेशनल फैडरेशन आफ इंडियन रेलवेमैन तथा भारतीय रेलवे मजदूर संघ इस आन्दोलन में भाग नही ले रहे है। मैं सदन को यह सूचित करना चाहता हू कि कोई गंभीर घटनाएं नही हुई है जिनकी वजह से रेलो के परिचालन पर तुरंत प्रभाव पडा हो और भी क्षेत्रीय रेलो पर स्थिति लगभग सामान्य है। सरकार ने यात्री तथा माल दोनो प्रकार की गाड़ियों के सामान्य संचालन को बनाये रखने के लिए सभी संभव उपाय कर लिये है।

जहां तक बोनस का प्रश्न है, माननीय सदस्यों को मालूम है कि वेतन, आय और मूल्य से संबंधित अध्ययन दल की रिपोर्ट में उल्लिखित सिफारशों तथा रेलवे जैसे सरकारी उद्यमों के कर्मचारी को बोनस दिये जाने के प्रश्न पर विचार करने के लिए एक मंत्री-मंडलीय उपसमिति का कहा गया था। इस संबंध में वित्त मंत्रालय द्वारा आगे विचार किया जा रहा है।

मैं रेल कर्मचारियों की यूनियनों पर यह जोर देता आ रहा हूं कि रेल कर्मचारियों को बोनस दिये जाने के प्रश्न पर विचार करने के लिए इसके व्यापक विहितार्थ को देखते हुए, सरकार को पर्याप्त समय दिये जाने की आवश्यकता है। विभिन्न मांगों का वार्ता द्वारा निपटारा करने का द्वार हमेशा खुला है। विगत दो वर्षों के दौरान कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के साथ वार्ता के माध्यम से रेल कर्मचारियों के अनेक वर्गों को फायदा पहुंचाने वाले बहुत से निर्णय किये गये हैं। जिन पर 125 करोड़ रुपये से अधिक की लागत आयेगी। बोनस का प्रश्न भी इसी तरह कोई ऐसी कार्यवाही किये बिना, जिससे राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था का तथा फलस्वरूप रेल कर्मचारियों के हितों का भी नुकसान हो, वार्ता द्वारा सुलझाया जा सकता है।

श्री मृणाल गोरे : उपाध्यक्ष महोदय, यह बड़े खेद की बात है कि जनता पार्टी की सरकार के आने के दो साल बाद भी रेल कर्मचारियों को बोनस के बारे मे कड़े कदम उठाने पड रहे है। यहां 7 मई को जो हुआ, उसको मैं प्रदर्शन तो नहीं कहूंगी बल्कि लोक सभा को पेटीशन देने के लिए रेल कर्मचारी यहां पर आए थे। उन रेल कर्मचारियों की आज मन: स्थिति क्या है उसको रेल मंत्री जी जरा समझ ले, यह मैं उनसे प्रार्थना करूंगी। 1974 मे इसी बोनस की माग को लेकर पूरे देश मे रेल कर्मचारियो की हड़ताल हुई थी और उस वक्त विरोधी दल मे रहने वाले जिन नेताओ ने रेल कर्मचारियों का अपनी हार्दिक सपोर्ट दी थी उनमे से कई नेता आज कैबिनेट मे बैठे है। ऐसी परिस्थिति मे रेल कर्मचारी दो साल तक इतजार करते रहे। जिन नेताओ ने उस समय रेल कर्मचारियो को पूरा सहकार दिया था उनमे केवल रेल मंत्री और उद्योग मंत्री, श्री जार्ज फरनेंडीस ही नही थे बल्कि आज कैबिनेट मे दूसरे मंत्री बैठे हुए है वे भी थे—चाहे अटल बिहारी बाजपेयी हो, होम मिनिस्टर श्री एच० एम० पटेल हों—इन सभी लोगो ने उस समय रेल कर्मचारियों की बोनस की माग की पूरी तरह से ताइद की थी।

मेरे पास लोक सभा की 9 मई, 1974 की प्रोसीडिंग्स है जिसम इन सभी नेताओ ने पूरी तरह से बोनस की माग की ताइद की थी। जनता पार्टी की सरकार के आने के बाद दो साल तक रेल कर्मचारी पेशेन्स के साथ बैठे रहे। रेल कर्मचारियों को, सरकार के अधीन जो दूसरे औद्योगिक सस्थान है, उनके कर्मचारियो के बराबर माना जाना चाहिए — यह उनकी माग है। इसीलिए वे बोनस की माग कर रहे है। आज हम देखते है विभिन्न राज्यो मे यातायात सम्बन्धी जितनी भी सस्थाये हैं, जो राज्य परिवहन मण्डल है, उन सभी के कर्मचारियों को बोनस मिल रहा है। ऐसी स्थिति मे यह कोई नही कह सकता कि रेल कर्मचारियो की बोनस की मांग वाजिब नही है। इस माग को लेकर 1974 मे रेल कर्मचारियो ने बहुत बड़ी सैक्रीफाइस की थी। उस समय सारे देश मे एकाधिकारशाही फोर्सेज के विरुद्ध लोकमत सगठित करने का काम रेल कर्मचारियो ने हड़ताल के माध्यम से किया था। आज हमे उनका धन्यवाद मानना चाहिए कि एकाधिकारशाही फोर्सेज का जो दमन चक्र रेल कर्मचारियो की हड़ताल के समय चल रहा था उसने पूरे देश की जनता का ध्यान खीच लिया था उसके साथ साथ बहुत बड़े पैमाने पर लोगो ने एकाधिकारशाही का विरोध करने का काम किया।

यहा रेल मंत्री जी कहते है कि 125 करोड रुपये की सुविधाए, खासतौर से उन्होंने रेलवे कर्मचारियो को दी है, इस का मैं मानती हू। इतना सब कुछ आपने किया है, मैं जानती हू और आप ने 50 हजार कर्मचारियो को सलेक्शन ग्रेड भी दिया है जो कई सालो से उन को नही मिल रहा था और आप ने दूसरी कई अच्छी बाते उन के लिये की है लेकिन फिर भी जो उन की बोनस की मांग है, जो उचित और सही मांग है, वह नही मानेंगे और उन को जब तक आप बोनस नहीं देंगे तब तक जो रेल कर्मचारी हैं, उन मे शांति और पूर्ण रूप से सहयोग करने की भावना नही रहेगी। आप ने बार बार इस सदन में कहा है कि रेल कर्मचारी पूरी तरह से आप के साथ सहयोग कर रहे है। किस तरह से रेल के एक्सीडेंट्स हो रहे थे और कुछ जानबूझ कर इस बात की कोशिश हो रही थी, उसके बाद रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आप ने जगह पर रखी है और उनकी मदद से आप इस को काबू मे कर सके है। आखिर रेल गाड़िया को अच्छी तरह से चलाने के लिए यह बहुत ही आवश्यक है कि कर्मचारियो का पूरा सहयोग आप को मिले। यह आप भी जानते हैं और मै भी यह जानती हू कि फेडरेशन जो मान्यता प्राप्त नही है उस ने कुछ आन्दोलन जारी किया है लेकिन जो मान्यता प्राप्त यूनियन्स है उन्होंने बहुत ही जिम्मेदारी से बहुत दिन राह देखकर अब 9 तारीख यानी कल यह फैसला किया है कि वह स्ट्राइक बैलेट ले ले और अगस्त तक यह बैलेट पूरा होने वाला है। मै यह भी कहना चाहूगी कि इस सवाल मे पूरी तरह से जाने के लिए सब-कमेटी नियुक्त हुई थी और उस कैबिनेट कमेटी ने, मैं निश्चित रूप से नहीं जानती कितने महीने विचार करने के लिए ले लिये। पूरा विचार करके क्या उस ने इस प्रश्न पर निर्णय ले लिया है? जहां तक मुझे मालूम है कि उसने यह निर्णय लिया है कि बोनस देना चाहिए। इस प्रकार का सुझाव कैबिनेट कमेटी ने किया है, यह सुनने मे आता है। अब अगर यह बात सही है, तो फिर क्या यह बोनस देने मे इतनी देर लग रही है और इस प्रश्न को ले कर आज स्थिति गभीर बनती जा रही है। तो मैं यह कहूगी कि रेल कर्मचारियों ने दो साल तक आप के साथ पूर्ण सहयोग किया है, उन की सहन शक्ति को अन्त तक मत ले जाइए और स्ट्राइक बैलेट होने से पहले ही इन का बोनस दीजिए और औद्योगिक कर्मचारियों के साथ उन को बराबर की परिस्थिति में लाने के लिये जो उन की माग है, उस को पूरा करिये। केवल 'विचार कर रहे है, इस से अब किसी का सतोष होने वाला नही है'। बहुत विचार आप कर चुके है। आखिर कब तक विचार करते रहेंगे। ऐसा न हो कि उन की विचार शक्ति और सहन शक्ति खत्म हो जाए। कृपया ऐसा मत करिए, और तुरन्त बोनस की माग को मजूर कीजिए।

एक सवाल यह उठ सकता है कि अगर रेल कर्मचारियो को देंगे तो दूसरे सभी सरकारी कर्मचारियों को देना पड़ेगा। मै कहती हू कि उस के ऊपर विचार करना है, तो वह तो आप ने जब सब कमेटी ने सुझाव दे दिया तब किया होगा। अब इस के बारे मे फिर से विचार कर रहे हो? यह भी मैं कहूगी कि बोनस देने के बाद उन से यह अपेक्षा रखेंगे कि जो पैसा उन को मिलेगा, उसमें से कुछ हिस्सा नेशनल डेवलपमेंट के लिए जाए। मैं ने इस बारे में यूनियन्स से बात नही की है लेकिन एक लैमैन की तरह, एक सामान्य व्यक्ति के नाते, मुझे लगता है कि रेल कर्मचारी इस बात का भी आदर करेंगे लेकिन बोनस उन का अधिकार है, जिस को आप को मंजूर करना पड़ेगा। तुरन्त आप को बोनस देने की भी व्यवस्था करनी चाहिए। मैं एक सवाल तो यह पूछना चाहती हूं कि क्या मंत्री महोदय इस का

जवाब देंगे कि उन की सहन शक्ति खत्म होने से पहले, आप का इस पर निर्णय होगा । यह मैं मंत्री महोदय से जानना चाहती हू ।

श्री राज नारायण : मै श्रीमती मणाल गोरे से एक गुजारिश करूगा कि वे यह समझ ले कि मजदूरों की 'विचार शक्ति' खत्म नही होगी, 'विचार शक्ति', 'कर्मशक्ति' मे परिणत हो जाएगी। यह वह मान ले ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप भाषा की तरमीम कर रहे हैं ।

प्रो० मधु दंडवते : श्रीमन्, मृणाल जी ने जो यहा भावना व्यक्त की है, उस के साथ सिर्फ मै ही सहमत नही हू बल्कि मैं समझता हू कि सारे रेल कर्मचारी और हमारे देश के अन्य कर्मचारी भी सहमत है । (व्यवधान) इसलिए पहले म दो-तीन बाते स्पष्ट करना चाहता हू कि इस सरकार की मार्च 1977 मे लगातार यह नीति रही है कि बोनस का जो सवाल है उसको क्रमश: सटिल करने की कोशिश की जाए। एमरजेन्सी के दौरान जो बोनस कानून खत्म किया गया था उसका पुनर्स्थापन करना हमारा प्रथम चरण रहा है।

Restoration of the old Bonus Act was the first step.

यह हम लोगो ने किया । यह मै इस सदन मे ही नही कहता हू बल्कि हजारो की तादाद मे जहा रेल मजदूर इकट्ठे होते है उन के सामने भी यह कहता हू कि क्रमश हम को इस सवाल को हल करना है और एक मर्तबा बोनस का पुराना कानून रेस्टोर करने के बाद जितना कवरेज उस कानून मे नही होता है उन के बारे मे हमें सोचना पडेगा । मै जानना चाहता था कि रेल कर्मचारियो, पी एण्ड टी कर्मचारियो और डिफेंस प्रोडक्शन के कर्मचारियो, इन सभी का सवाल उठेगा । इस सवाल को हल करने मे थोडी देर लगेगी । इस के लिये मै यकीन दिलाना चाहता हू ।

1974 मे जब इस सवाल पर स्ट्राइक किया गया था और जिसका नेतृत्व श्री जार्ज फर्नान्डीस ने किया था तो उस समय श्री जार्ज फर्नान्डीस ने श्री ललित नारायण मिश्र को तिहाड जेल से खत लिखा था और विरोधी दल के लोगों मे से भी श्रीमती गांधी से उस वक्त मिला था । उस वक्त हम लोगों ने साफ तरीके पर यह कहा था कि बुनियादी सिद्धांतों को मानने के बाद, अगर अर्थ-व्यवस्था की कोई दिक्कत हो तो फेज्ड तरीके से एक-एक मांग मान ली जाए जिस में हमारा कोई विरोध नही है । यह श्री जार्ज फर्नान्डीस ने संघर्ष समिति के तौर पर और विरोधी दल की ओर से मैंने खुद जाकर भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को उस समय कहा था।

To quote my own words, I told the former Prime Minister that:

"Leaders of this Struggle realise that if there are financial and economic difficulties, you tell us, in a phased manner, these demands could be accepted and how the problems could be sorted out."

मै यकीन दिलाना चाहता हू कि मणाल जी को रेल मंत्री की हैसियत मे रेल कर्मचारियो की समस्याओं की तरफ देखने का मेरा रवैया सहानुभूतिपूर्ण रहा है । इस मे गवर्नमेंट के कई डिपार्टमेंट्स का सवाल आता है । इस बोनस के सवाल को हल करने मे कुछ समय लगेगा । मैंने जान-बूझ कर बोनस के सवाल को अन्य सवालो से अलग कर दिया है । इस के अलावा और जितने सवाल हो सकते थे, पिछले दो सालो मे हम ने उन को हल किया है । मुझे गर्व है कि जनता सरकार के आने के बाद से, पिछले दो सालों मे 126 करोड की मांगो को मजूर किया गया है । इस को इन्टेक एफिलियेटिड आर्गेनाइजेशन्स ने और विरोधी दल मे काम करने वाले लोग जो यूनियने चलाते है उन्होंने भी कई मर्तबा हमारे सामने कहा है कि हम यह जरूर मानते है कि पिछले दो साल मे जितनी मागे मजूर हुई है उतनी मांगे पिछले 125 सालो के किसी भी साल का ले लीजिए, जब कि दो सालो मे इतनी मागे मजूर नही हुई है। इतनी मागे मजूर करने का काम पिछली किसी भी सरकार ने 125 सालों मे किसी साल मे नही किया । हम क्रमश. इस सवाल को भी हल करने की कोशिश कर रहे है ।

अब मै बोनस के सवाल की ओर आता हूं। जिन संस्थाओ ने बैलट का फैसला किया था—दोनों ही फेडरेशन के लोग फैसला करने के बाद मुझे मे मिले थे । पहले इन्टैक एफिलियेटिड नेशनल फैडरेशन ने फैसला किया था कि पहली मई को नोटिस देंगे और 31 मई को स्ट्राइक शुरू होगी। लेकिन उस के बाद उन्होने अपनी बैठक की और यह फैसला किया कि राज्य सभा और लोक सभा मे मैंने जिस ढग से इस सवाल को रखा था, उस पर विश्वास रख कर के हम आपको और ज्यादा समय देना चाहते है । यह उन्होंने मुझे लिखित पत्र मे भी लिखा है ।

13.00 hrs

हमें आशा है कि आप कुछ कर पायेंगे, सरकार कुछ कर पाएगी और रेल मंत्रालय पर भरोसा रख

[प्रो0 मधु दंडवते]

कर हम मुल्तवी रखते है । यह हमारा निर्णय है । उन्होंने स्ट्राइक का डिसिशन पोस्टपोन कर दिया है...

श्रीमती मृणाल गोरे : करवा नही सकते थे इसलिए पोस्टपोन किया है ।

PROF. MADHU DANDAVATE: I am coming to it. I don't want to cast any aspersion on any organisation. Here I am functioning as a Railway Minister.

AN HON. MEMBER: It is good of him.

प्रो0 मधु दण्डवते : जहां तक आल इंडिया रेलवे मेन फेडेरेशन का सवाल है उन्होंने जनरल काउंसिल में फैसला किया है कि सरकार को काफी मौका देना चाहिये । उन्होंने जो फैसला किया है वह भी हडताल करने का नहीं है । उन्होंने निर्णय यह लिया है कि 31 अगस्त तक हम बैलट देंगे । आगे चल कर उन का निर्णय यह है कि 31 अगस्त तक बैलट का काम पूरा करने के बाद अपनी वर्किंग कमेटी की बैठक उसके बाद बुलाएंगे और आगे चल कर क्या करना है उस के बारे में हम कारंवाई तय करेंगे । बीच में हम लोग रेल मंत्रालय के साथ बात चीत करेंगे । इस फैसले के चंद घंटों के बाद वे रेल भवन में मेरे पास आए और उन के साथ मेरी एक घंटे तक कल बैठक हुई । उन्होंने मुझे यकीन दिलाया है कि हम लोगों ने यह निर्णय लिया है लेकिन हम लोगो पर फिर भी आप भरोसा रखें और हमारा भी आप पर विश्वास है और हमारा विश्वास है कि स्ट्राइक की नौबत नहीं आएगी और जिन्होंने हमारी स्ट्राइक का नेतृत्व पुराने जमाने में किया है और जो आज सरकार चला रहे है हमारा विश्वास है कि इसको देखते हुए आप कैबिनेट के सामने, सरकार के सामने इस सवाल को रखेंगे और शायद हड़ताल करने की नौबत नहीं आएगी । उन्होंने यह भी कहा है कि हम नैगोशिएटिड सैटलमेंट के हक में हैं । इस में गिव एंड टेक भी हो सकता है । इस प्रकार की नेगोशियेसन्ज स्ट्राइक बैलट से पहले हो सकती है ।

जहां तक वर्क टू रूल का सवाल है उन्होंने स्ट्राइक शुरू नहीं की है । यह गलत इनफर्मेशन लोगों की है । एक आर्गेनाइजेशन है आल इंडिया रेलवे एम्प्लायीज कनफेडेरेशन उन्होंने वर्क टू रूल, नियम के अनुसार काम करने का आन्दोलन शुरू किया है । स्ट्राइक शुरू नहीं की है । मैं किसी की नियत पर हमला नही करना चाहता हूं । लेकिन एक दो दिन गाड़ियां आने में जो दिक्कत हुई है उस का एक कारण यह भी है कि गाजियाबाद के नजदीक एक रेल एक्सीडेंट हुआ है और उत्तर प्रदेश मे पावर की दिक्कत होने की वजह से ओवर हेड वायर्ज काम नहीं कर पाई है, इस लिए कुछ गडबड हो गई है । अलीगढ में कुछ गड़बड़ हो गई है । उसकी वजह से गाड़ियों के आने में कुछ देरी हुई है

श्री कृष्णचन्द्र हाल्दर (दुर्गापुर) : हावड़ा में क्यों देरी से आ रही है ?

प्रो० मधु दण्डवते : बहुत अच्छी इनफर्मेशन आपने दी है । वर्क टू रूल शुरू होने से पहले भी हावड़ा और कलकत्ता में गाड़ियां देर से आ रही थी तो इस का अर्थ यह हुआ कि वर्क टू रूल का असर नही है बल्कि दूसरे इसके कारण रहे है । वर्क टू रूल आन्दोलन आठ तारीख से शुरू हुआ है और इसको आल इंडिया रेलवेमैन्ज फेडेरेशन, एन० एफ० आई० आर० ने स्पोर्ट नहीं दी है और ना भारतीय मजदूर संघ ने स्पोर्ट दी है । उसका कोई ज्यादा असर भी नहीं हुआ है । हम लोगो की कोशिश होगी कि वैगन मूवमेंट और पसेंजर मूवमेंट मे किसी प्रकार की बाधा न पहुंचे ।

[illegible]

मै पहले ही निवेदन कर चुका हूं कि कैबिनेट सब-कमेटी के सामने यह सवाल है, अर्थ मंत्रालय के साथ भी सम्पर्क हम रखे है और हमारी लगातार कोशिश होगी कि हम लोगो ने जो वादे किए है उन को ध्यान मे रखते हुए और रेलों की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए और साथ ही साथ मजदूर संस्थाओं का सहयोग ले कर और कम्प्रोमाइज करके उन की मांगो को जहां तक हो सके पूरा किया जाए । मैं माननीय सदस्या और सदन को भी विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस सवाल को नैगोशिएटिड सैटलमेंट के जरिये जल्द से जल्द हल करने की हम कोशिश करेंगे।

श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली सदर) : मैं मंत्री महोदय को बधाई देता हूं कि दो बरस मे जो उन्होंने किया है वह बहुत सराहनीय है और शायद पिछले तीस बरस मे इतना काम कभी नही हुआ है ।

श्रीमती मृणाल गोरे ने कहा कि 1974 में जो रेलवे स्ट्राइक हुई उस में माननीय मंत्री जी, जार्ज फर्नान्डीज, माननीय वाजपेयी जी, माननीय समर मुखर्जी, और बहुत सारे लोग शामिल थे जिन्होंने बोनस की मांग को रखा था पर पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी में जैसे कोइन की दो साइड होती हैं उसी तरह से मेम्बरस की तीन साइड्स होती है एक साइड तो जब अपोजीशन में बैठता है, दूसरे जब सरकारी पक्ष में आता है तो थोड़ा बदल जाता है, और जब मंत्री

होता है तो थोड़ा और बदलता है। और जनता पार्टी में चौथा भी हिस्सा है कि प्रधान मंत्री या उप प्रधान मंत्री होता है तो वह चौथी साइड होती है। क्योंकि यह मंत्री और बाकी लोगों में सभी साइड अलग अलग हैं। सिद्धान्त रूप में यह सरकार स्वीकार करे कि हम बोनस की मांग को स्वीकार करते हैं। लेकिन मजदूरों को साफ तौर से बता देना चाहिये कि हमारे देश की जो आर्थिक स्थिति है वह ऐसी नहीं है कि जिस में हम इतना खर्चा अभी कर सकें। या उस के बाद पी० ऍंड टी० के लोग, डिफेंस के लोग और कर्मचारियों के लिये इतना रुपया सरकार दे सके ऐसी हमारी अवस्था नहीं है। और यह भी मंत्री महोदय से मांग करूंगा कि जो अनुशासनहीनता है यह भी खत्म होनी चाहिये, और जो लोग ट्रेड यूनियन के नाम से कंप्राम कर रहे हैं इस को भी सख्ती से निपटाया जाय। पिछले एक मास से देख रहे हैं कि कोयला नहीं आता, रेल वैगन नहीं हैं। अभी तक यह नहीं बता पाये कि कहानी क्या है . . .

SHRIMATI AHILYA P RANGNEKAR: Employees are not responsible; trade unions are not responsible.

SHRI KANWAR LAL GUPTA: I want that there should be strict discipline among the railway employees and they should be frankly told that they have to work hard and harder.. ..(*Interruptions*). I want the Minister to enforce discipline and the workers should be told frankly that no indiscipline would be allowed in the name of trade union or anything. There should be no harassment to the passengers; there should be no corruption. They should work hard and earn; railways should not run into losses. Then, we can consider their demand for payment of bonus. Unless they earn, they will not be allowed this. . . . (*Interruptions*). But at the same time, I would request the hon. Minister to tell them that as a matter of principle, we are for bonus, but we are not in a position to give it because that will create many complications. We have to think about P&T, Defence. . . . (*Interruptions*).

MR. DEPUTY-SPEAKER: Members should have some restraint on themselves.

SHRI KANWAR LAL GUPTA: I want to ask certain questions. Let the Minister write them down. He says, "We have taken steps to meet the situation". Suppose there is no agreement. What specific steps have Government taken, or they propose to take in future, to meet the situation. Again, is it a fact that the Finance Ministry has not accepted the demand for bonus? It has appeared in the Press that the Finance Ministry has rejected, and turned it down. Is it a fact that the Political Affairs Committee of the Cabinet has also not approved it? Thirdly, you want to have negotiations—but with whom? Will you call the representatives of all the trade unions—or of only some unions? I want that the representatives of all unions should be called. Fourthly, will this issue of bonus be applicable only to the workers working in the workshops, or even to the workers in the Railway Board? Next, what will be the financial implications, so far as Railways are concerned? If you give it, naturally you will have to give to P&T and Defence. What will be the total financial implications? I again want to repeat: the Minister should also be emphatic when he says, "Bonus, in principle, I agree. We will try to accommodate". He should be firm at the same time, because nobody should be allowed to create chaos in the country.

PROF. MADHU DANDAVATE: Before I come to the 3 or 4 questions which he has raised, let me make one thing explicitly clear. As far as indiscipline is concerned, even the organized trade unions believe that whenever they undertake any agitation, they should give proper notice. (*Interruptions*) This is not an organised trade union movement. You have to make a distinction between sporadic action undertaken by unorganized sections of labour and the legitimate, organized trade union activity undertaken by trade union organizations, whether they are recognized or unrecognized. There must be a distinction between the two.

[Prof. Madhu Dandawate]

Sometime back I received complaints from the Chief Ministers of Tripura and West Bengal the certain wagon movements had been affected by certain sporadic actions. We went into the problem and found that some of the sporadic actions—pinpricks as we call them—were not by any organized trade unions, but by unorganized sections. As far as such pinpricks are concerned we dealt with them very sternly, and we shall continue to deal with them very sternly. I am doing this after consultations with trade unionists, because it is not a legitimate trade union activity. Therefore, we must try to distinguish between the legitimate, organised trade union activity sponsored by the trade unions and some pinpricks and catcall actions indulged in by some irresponsible elements which belong to unorganized sections. During March last when such pinpricks were given and as a result, Tripura and West Bengal suffered the most, we took very stern and firm action; and we have made it very clear to the trade unions concerned that such pin prices would not be tolerated.

Coming to the question of bonus, the hon. Member has raised 3 or 4 questions. His first question was "In the event of any chaos created, what action will be taken". He has misunderstood our entire approach. I made it clear that I have full confidence in the trade union organisations, and I know that they have taken a decision to take a strike ballot. It will be possible for us to settle this problem across the table. Therefore, I shall not make any imaginary proposition that they are going to create chaos and we are going to deal with it. As far as sporadic actions and indiscipline are concerned, even to trade unions I have said that we shall never tolerate any indiscipline that will result in loss of productivity. As regards sensitive zones, if the coal does not reach in time, the production will suffer. In North-eastern States like Tripura and Mizoram, if the rice does not reach them in time before the monsoon, they are likely to suffer during the entire year. Therefore, any sporadic activity which will create dislocation in the economy we shall deal with it very firmly. But I shall not imagine—if a legitimate trade union strike is going to take place with due notice right from now,—what action I am going to take.

(Interruptions)

SHRI KANWAR LAL GUPTA: Will you approve strike by Government servants at all?

PROF. MADHU DANDAVATE: You are raising a very vital issue.

AN HON MEMBER: They have got a constitutional right *(Interruptions)*.

PROF MADHU DANDAVATE: As far as the present position is concerned and the constitutional provisions are concerned and all the laws that exist are concerned, there is a certain procedure prescribed by laws even for action by railway employees or any one else. They have to take a ballot, and follow it up by giving a due notice. After that there is a room for negotiations. And as far as railway employees are concerned, there are certain forums like PNM and JCM that are available; and many problems we are able to settle there. I have confidence that they will fully utilise these forums which are available; and with the machinery that is available, it will be possible to sort out a number of issues without plunging the workers into a strike action. Therefore, to your hypothetical question I do not want to give any reply.

As far as the decision taken in the matter by the Finance Ministry, the decision taken by the Cabinet Sub-Committee is concerned, the hon. Member is a knowledgeable person. He is fully equipped with the knowledge and functioning of the parliamentary democracy; and he knows it

very well, that those of us who have taken an oath of secrecy cannot leak out some of the intermediary decisions that have been taken in the Cabinet. I cannot reveal what the Sub-Committee has decided When the questions are being sorted out in the Finance Ministry, I can, however, say one thing very clearly that so far the Finance Ministry has not taken a final decision. In fact before I gave my reply in the Rajya Sabha and Lok Sabha, to the railway budget demands, I went to the Finance Minister and tried to find out from him what exactly must be the answer, and with full consultation with him, I had said that the Sub-Committee was processing the issue The Finance Ministry had to examine it; and it is at that stage the problem is there I canont reveal to this House what has happened in the Sub-Committee You understand that, but he does not realise that though he believes in that I do not want to cast aspersion on that He believes in that

SHRI KANWAR LAL GUPTA: Why I asked this question is because this news appeared today in a paper that the Finance Ministry is opposing it on a peculiar pretext, because it will help the urban people. That I do not want. I had no intention to ask. I had avoided it. Since you accuse me being a Member of the Ruling Party, I want to know how your Ministers are behaving; how you are behaving? How the Ministers are talking before the public I want to know, because you accuse the Members; you do not accuse the Ministers.

PROF MADHU DANDAVATE: I am not accusing.

SHRI KANWAR LAL GUPTA: I want that there should be no strike, but there should be some sort of a forum where all the grievances of the workers should be settled.

PROF. MADHU DANDAVATE: I am very sorry if my hon. friend and colleague Mr. Kanwar Lal Gupta felt that I cast any aspersion. In fact, I said that I have full faith in his knowledgeability and that he himself believes in the functioning of the parliamentary democracy. Some decisions of the Cabinet Sub-Committee, interim decisions of the Cabinet Sub-Committee, I cannot reveal.

MR. DEPUTY SPEAKER: He just took a chance in the dark.

PROF. MADHU DANDAVATE: If, inadvertenty any remarks of mine have hurt him, I would withdraw even those inadvertent remarks. So, this is the position. As far as negotiations are condemned with whom the negotiations are carried on? There are various statutory forums like JCM and PNM. There are certain recognised organisations. There was some demonstration by the Bharatiya Mazdoor Sangh claiming that they should also get the recognition. They went back happily yesterday when I assured them that even pending Industrial Relation Bill, because it will take a long time,—we have to take the consent of all, if all the existing unions whether recognised or un-recognised, accept the proposition, then as an experimental measure let us go ahead with the problem of settling the recognition issue on the basis of referendum, that is ballotted by the workers, I shall be prepared for it. I am happy to know that a number of organisations—All India Railwaymen's Federation, Bharatiya Mazdoor Sangh, they have given in writing that they are prepared for such a referendum. I hope if I am able to sort out that issue, then whether to include or whether to exclude, that issue can be eliminated. This is in connection with this.

As far as the principle is concerned he said, "Are you prepared to announce this here that we accept this in principle for Railwaymen." It means in the existing jurisdiction of

[Prof. Madhu Dandavate]

the Bonus Act if we already include Railways, then the question does not remain controversial at all. But I am not authorised to make that announcement unless the Cabinet has taken a final decision. Unfortunately, I am not accustomed to go on making pronouncement unless a final decision is taken. I shall have to await the decision. But I shall contribute my mite in settling the issue finally and firmly.

श्री विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिणी दिल्ली) अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने कहा है कि सारी सिचुएशन बिलकुल नार्मल है। .... (व्यवधान) ... वर्क टू रूल के बावजूद हालात नार्मल है और कोई इस मे किसी तरह की गड़बड़ नहीं हो रही है। लेकिन आज के पेपर्स के अंदर जो खबरे है और खास तौर से "हिन्दुस्तान टाइम्स" के फ्रन्ट पेज पर जो खबर है, उस को आप देखे :

"

" 'Sabotage' at station

Attempted sabotage by agitating railwaymen delayed all important incoming and outgoing trains here today.

Near Ghaziabad, a Bareilly-Delhi Passenger train was twice derailed. The trains coming behind were delayed. Thousands of passengers were stranded.

Railwaymen were obstructing automatic signals creating confusion. The signals at some places did not operate with the result the trains did not move.

Commuters crowded inquiry counters. Late this evening, lights went out for two-three minutes plunging the entire Delhi Main station in darkness creating confusion and chaos.

The platforms were strewn with luggage and commuters. The notice board said several trains were running late by three to eight hours."

अध्यक्ष महोदय, इन हालात में मंत्री महोदय का यह कहना है कि सिचुएशन में कोई फर्क नहीं है और सब काम बिल्कुल ठीक, नार्मल चल रहा है कहां तक सही है ? मैं उन को याद दिलाना चाहता हूं कि हमारे एनर्जी मिनिस्टर ने कई बार इस बात को रिपीट किया है कि क्योंकि जो वर्क है रूल चल रहा है नार्थ ईस्टर्न एरिया में, उस की वजह से सारे हिन्दुस्तान में कोयला नहीं पहुंच रहा है और कोयला नहीं पहुचने की वजह हो सकता है कि हिन्दुस्तान में किसी दिन कैआटिक कंडीशन आ जाय। यह कोई साधारण बात नहीं है। मैं मंत्री महोदय से रिक्वेस्ट करना चाहता हू कि जब बोनस हमें देना है और जब यह तय किया है कि बोनस की मांग को हम मानते हैं तो बोनस दिया क्यों नहीं जाता है ? उस को इतना डिले करना और इतना घुमाना फिराना जिस मे यह स्थिति हो जाय कि सौ प्याज भी खाना और सौ जूते भी खाना, उन का एजीटेशन भी हो जाय और उन के झगड़े भी हो जाय और उस के बाद बोनस दें, यह कौन सी समझदारी की बात है ? समझदारी का तरीका यह है कि अगर आप को बोनस देना है तो उस में इस से पहले कि वे लोग एजीटेशन का रवैया अख्तियार करें, लाखों आदमी दिल्ली मे आए और उनके डिमास्ट्रेशन हो और फिर यह हो कि हम उन को बोनस देते है, बजाय इस के जब आप बोनस देने जा ही रहे है, जैसे आप डबल रोटी के कारखाने मे जो डबल रोटी बनाने वाले हैं उन को तो आप बोनस देते है गवर्नमेंट अडरटेकिंग मे और जो रेल गाड़ी का ड्राइवर है, जो इजन चलाता है, जिस को इतनी मुश्किल झेलनी पड़ती है, उस को आप बोनस नही दे रहे है, तो यह कोई पैरिटी की बात भी नही है और दूसरी कोई चीज भी इस मे नही है, यह सिद्धान्त रूप मे स्वीकार करने की बात नहीं है, आप को बोनस देना है और उस का मेथड क्या होगा, वह आप डिक्लेयर करें और उस मे उन का कोई इस तरह का मौका नही देना चाहिये।

मै यह भी मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि आखिर इस बात को भी वह ध्यान मे रखें कि हिन्दुस्तान में कोई पार्टी किस तरह से कैआटिक हालात पैदा कर रही है, आपने देखा कि पुलिस की हड़ताल हो रही है, आप ने यह भी देखा कि जगह जगह पर स्ट्राइक्स कराने के लिए जो साजिश हो रही है। जब आप बोनस देने जा रहे है तो यह मौका क्यो देते हैं कांग्रेस (आई) के उन लोगों को, संजय गाधी और उन के दूसरे लोगों को जो सारे हिन्दुस्तान के अंदर एनार्की फैलाना चाहते है और उसका बहाना ढूंढ रहे है अभी जो हालत हुए और जिस तरीके से झगड़े हुआ अलीगढ़ के स्टूडेंट्स के साथ जो हुआ, जिस के बारे मे बात आएगी, यह सब उसी साजिश का नतीजा है और मंत्री महोदय इस बात को देखे। वह कहते है कि कैबिनेट फैसला करेगी, बाद में करेगी और उस की मेथडालाजी ढूंढी जा रही है और उधर से नोटिस आ गया रेफ्रेंडम होने का तो यह क्या कोई ऐसी बात है कि हमें रेफ्रेंडम के डर से या किसी और बात से देना है या गवर्नमेंट की अपनी मर्जी से देना है जब कि प्रिंसिपल के तौर पर हमने खुद इस बात को माना है। इन दोनों में बहुत फर्क है। मंत्री महोदय इस फर्क को समझें। लोगों की एजीटेशन करवा कर और करोड़ों पैसेंजर्स को नुकसान पहुंचा कर बाद में बोनस का एनाउंसमेंट करेंगे.

इस का क्या फायदा है ? फौरी तौर पर एक दो दिन में इसको कैबिनेट में ले जायें और बोनस के बारे में डिक्लेयर करें। मेथड का फैसला बाद में होता रहेगा। यही मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं।

प्रो० मधु दण्डवते : पहले तो मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय सदस्य ने बोनस के वजाए शुरु में कोयले के वितरण का सवाल उठाया। मैं इतना ही कहूंगा कि जब मैंने यह कहा कि परिस्थिति नॉयर एबाउट नामल है, परिस्थिति सामान्य है, तो वैगन मूवमेण्ट के बारे में अन्य दिक्कतें हैं जिनकी वजह से कई जगह पर कोयला कम है और जहां कोयला है वहां वैगन कम हैं—इन कारणों की वजह से जो दिक्कतें हैं उनका मैंने जिक्र नहीं किया, मैंने कहा कि 8 तारीख को जो "वर्क टू रूल" मूवमेन्ट शुरु हुआ उसकी वजह से कोई ज्यादा डिसलोकेशन नहीं हुआ है। डिस्ट्रीब्यूशन पर आज जो भीड़ हुई है जिसका चित्र 'टाइम्स आफ इंडिया" और दूसरे पत्रों में आया है उसका कारण वर्क टू रूल नहीं है। यह पूरी में पावर की कटौती से कुछ तकलीफ पैदा हुई है या एक दो जगह पर माइनर डिरेलमेन्टस हुए (व्यवधान) मैंने वैगन्स के बारे में यह बताया कि एक दो दिन में जो हुआ उसकी वजह अलग है। 8 तारीख को जो वर्क टू रूल मूवमेन्ट शुरू हुआ है उसका इस पर ज्यादा असर नहीं हुआ है।

बाद में उन्होंने कहा कि बोनस अगर देना है तो ग्रेस के साथ देना चाहिये। लम्बे अरसे तक झगड़ा करने के बाद जुलूस आने के बाद परिस्थिति खराब करने के बाद बोनस देना अच्छा नहीं है। मैं उनकी भावनाओं के साथ सौ फीसदी सहमत हूं। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं बताना चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी हम फैसला कर लेंगे और जब फैसला होगा तो ग्रेस के साथ उसको लोगों के सामने रखेंगे तथा उस पर अमल करेंगे उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। जब फैसला हो जायेगा तो उस पर अमल करने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। लेकिन जैसा कि और कई लोगों ने कहा, दूसरे डिपार्टमेन्ट्स का भी जिक्र करना है इन सब चीजों को देखते हुए और जो हमारे आर्थिक संसाधन है, रिसोर्सेज हैं उनको देखते हुए फेज में इसको हल करना है या एक ही क्रम में हल करना है— इस पर सोचना होगा। (व्यवधान) जहां तक रेल कर्मचारियों का सवाल है बोनस पर 75 से 80 करोड़ का इम्पीडेंस होगा— पर ईयर।

AN HON. MEMBER: Per Year?

PROF. MADHU DANDAVATE: Yes. You cannot give bonus once in 50 years. It has to be given every year.

एक साल के लिए 75 से 80 करोड़ का खर्चा इस पर होगा।

दूसरा सवाल जिसका जवाब मैंने नहीं दिया था रिट्रास्पेक्टिव जवाब देना चाहता हूं उन्होंने कहा कि फैसला भी हो जाय तो वह क्या हो सकता है, क्या सिर्फ वर्कशाप में काम करने वाले ही इसमें होंगे तो उसका फैसला हमको करना पड़ेगा। लेकिन जब फैसला होता है तो उसमें एक ही इंडस्ट्री में दो प्रकार के कर्मचारी कभी नहीं माने जाते हैं। बैंकों में और एल आई सी में मैनअल वर्कर और दिमाग से काम करने वाले कर्मचारियों में कोई भेद नहीं किया जाता है। किसी पब्लिक सेक्टर में ऐसा भेद नहीं किया जाता है। इसलिए जो सुझाव है वह मंजूर हो या न हो लेकिन इस तरह का डिविजन कहीं पर नहीं है यह बात मैं साफ करना चाहता हूं।

श्री अमरसिंह बी० राठवा: (छोटा उदयपुर) आग लग जाने के बाद कुआ खोद कर पानी निकाला जाए—ऐसा हर बात में हो रहा है। आज देश में सत्याग्रह, हड़ताल, डकैती, आग लगाना,—यह बातें बहुत बढ़ गई हैं। यह बातें हो जाने के बाद समितियां बनती हैं और उसके बाद काम शुरू करने का वचन दिया जाता है। 8 मई को बोट क्लब में रेलवे कर्मचारियों के सामने और सत्याग्रहियों के सामने उद्योगपतियों के चाहते उद्योग मंत्री जी ने कहा था कि 2 साल में रेलवे कर्मचारियों के लिए और मजदूर संघ के लिए कुछ नहीं हुआ। यह उन के मंत्री का कहा हुआ है मैं नहीं कह रहा हूं। यह रेलवे कर्मचारियों की और उन के संघ की मांग है और आप ने भी वचन दिया हुआ है कि बोनस देंगे। उन्होंने ये वचन दिये हुए हैं

(1) बोनस देने का वचन,

(2) अन्य सार्वजनिक स्थानों के समतुल्य वेतन देने का वचन,

(3) पद मूल्यांकन का वचन,

(4) महंगाई भत्ते देने का वचन,

(5) श्रमिकों को और मजदूरों का अस्थायी रखने की प्रथा को समाप्त करने का वचन।

ये जार्ज फर्नाण्डीस साहब ने भी मांग की हुई है और सरकार बनने के वक्त ये वचन दिये हुए थे लेकिन ये अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। कब इनको पूरा कर रहे हैं ?

प्रो० मधु दण्डवते मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। एक फैरिस्त इनके सामने रखना चाहता हूं कि जनता सरकार के आने के बाद रेलवे मंत्री की हैसियत से कितनी मांगे मंजूर की हैं और कितना पैसा उन को दिया है। यह फैरिस्त मैं रखना चाहता हूं। जहां तक श्री जार्ज फर्नाण्डीस की बात है, उन के भाषण की रपट को मैंने पढ़ा है और जिस विशाल जुलूस में जो लोग थे, उन लोगों ने भी मुझे बताया है कि जार्ज फर्नाण्डीस साहब ने यह भी उन मजदूरों को बताया कि बोनस का सवाल हल होने वाला है लेकिन यह भी ध्यान रखें कि जनता सरकार ने उन को 126 करोड़ रुपये दिलवाए हैं। यह उन्होंने उस विशाल रेली में कहा है। यह नहीं कहा कि आप के सवाल हल

[प्रो० मधु दण्डवते]

नही हुए और जार्ज फर्नाण्डीस साहब ने जो टोटल फीगर्स दिये हैं, उन का बैक भ्रप मे रेलवे मत्री की हैसियत स यहा पर देना चाहता हू ।

Selection Grade for Class IV employees, 50,000 posts, for the first time in 125 years Rs. 1.50 crores; restructuring of Class III posts, 41,000 posts Rs. 10.5 crores; revision of incentive bonus rates for workshop staff Rs. 10 crores; revision of running allowance for loco staff from 25 per cent to 40 per cent Rs. 14 crores; sancation of 2,700 posts for implementation of 10-hour rule for loco staff, which was violated by the previous Government, Rs. 2 3 crores; sanction of 10,000 additional posts for implementation of Miabhoy Award Rs. 8 crores carriage and wagon staff, upgradation of posts in ratio of 50:10:40. Rs. 6 crores, Railway workers' Classification Tribunals' Interim Report, Benefit to Artisan Staff, Rs. 10 crores Absorption of commissioned bearers as regular employees (1,012 posts) Rs. 0.3 crores; adjustment of 1974 strike absence against leave due Rs. 6 crores; 40 per cent promotion quota for Class II officers instead of 33 1/3 per cent; all temporary officers confirmed; Cadre review for Class I undertaken; dearness allowance three additional instalments; recently another instalment has been sanctioned the cost is Rs. 66 crores; Special Grant for Staff amenities Rs. 15 crores; revision of night duty allowance rates Rs. 6.8 crores; increase in rates of payment for work on National Holidays Rs. 1.23 crores; Upgradation of 7,000 Class III posts Rs. 1.75 crores.

एक खुशी की खबर मैं और देना चाहता हूं । 90 साल पहले शिकागो मे मजदूरों का एक जुलूस निकला था कि 8 घंटे से ज्यादा काम नही लेना चाहिए, तो उस वक्त उन पर गोली चली थी और उन के खून से एक नया इतिहास बना और सारी दुनिया के मजदूर वक्ताओं ने कहा था 1 मई को कि 8 घंटे का दिन शुरू करें, 8 घंटे की ड्यूटी करो और इसी 1 मई को अहमदाबाद में सर्वोदय एक्सप्रेस का उदघाटन करते हुए, मैंने घोषणा की थी कि सब मे निम्न श्रेणी का जो गैंगमन है, जिन की तादाद 2 लाख 12 हजार है, उन के लिए 1 मई से 8 घंटे का दिन रहेगा ।

13.34 hrs.

COMMITTEE ON PAPERS LAID ON THE TABLE

NINETEENTH REPORT

SHRI KANWAR LAL GUPTA (Delhi Sadar): I beg to present the Nineteenth Report (Hindi and English versions) of the Committee on Papers laid on the Table.

STATEMENT *RE*. REDUCTION IN PRICES OF COTTON CLOTH AND COTTON YARN

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI GEORGE FERNANDES): Sir, Government has been viewing with concern the trend of rising prices of cotton cloth and yarn in recent months, particularly in the context of the falling prices of cotton This was first brought to the notice of the industry which in its defence pointed out that while cotton prices have, no doubt, fallen, costs of other inputs like wages, dyes and chemicals, fuel and other overheads have been increasing at the same time, which has made up for the fall in prices of cotton. The industry also drew Government's attention to the power cuts which have been imposed in various parts of the country and wage increases which have been negotiated in some major textile concentrations.

Claims of the industry were cross-checked with the experience in the National Textile Corporation and it was found that the escalation in prices was not justified by any means. I, therefore, held discussions with representatives of the textile industry in a meeting convened by me in Bombay on 10th March 1979. I urged upon the industry that they should take immediate steps for bringing down the prices of cotton cloth and cotton yarn.

Consequent upon this meeting, the Indian Cotton Mills' Federation res-